Vol 6, Issue 10, 2023 **Impact Factor: 5.099** DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2023.6.10.6812

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता स्तर एवं शैक्षिक विकास योजनाएं -एक भौगोलिक अध्ययन

वीणा कुमारी

शोधार्थी (भूगोल)
वाई.बी.एन. विश्वविद्यालय, रांची

डॉ. कैलाश नाथ सिंह

सह – प्राध्यापक, भुगोल विभागाध्यक्ष
वाई.बी.एन. विश्वविद्यालय, रांची

सारांश:

यह अध्ययन सामाजिक-आर्थिक विकास में साक्षरता के महत्व की जांच करता है, जिसमें झारखंड के रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। साक्षरता व्यक्तियों को सशक्त बनाने, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी है। हालांकि, भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक बाधाएं, विशेष रूप से ग्रामीण रांची के हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए, शैक्षिक पहुंच में रुकावट उत्पन्न करती हैं। यह शोध शैक्षिक विकास योजनाओं, जैसे कि सरकार की सर्व शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है, जो इन बाधाओं को दूर करने के लिए बनाई गई हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग करके उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जहां शैक्षिक सुविधाओं तक सीमित पहुंच है, जो नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह अध्ययन साक्षरता में सुधार लाने और समान शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने के लिए लक्षित रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु: साक्षरता, सामाजिक-आर्थिक विकास, भौगोलिक बाधाएं।

1. प्रस्तावना

साक्षरता का महत्व किसी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को आकार देने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। साक्षरता केवल एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण भी है जो व्यक्तियों की क्षमताओं को बढ़ाता है और समुदायों को सशक्त बनाता है। झारखंड की राजधानी रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में, साक्षरता आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार, और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, इस क्षेत्र को भौगोलिक परिदृश्य, सामाजिक-आर्थिक विषमताओं, और शैक्षिक बुनियादी ढांचे की सीमित पहुंच के

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

कारण अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।यह अध्ययन रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के स्तर और शैक्षिक विकास योजनाओं के प्रभाव पर केंद्रित है, जिसमें उन भौगोलिक कारकों पर जोर दिया गया है जो शिक्षा तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। झारखंड, प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विविधता में समृद्ध राज्य है, जिसमें इसकी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। रांची जिला, जो राज्य के केंद्र में स्थित है, एक विविध भूभाग प्रस्तुत करता है, जिसमें पठार, पहाड़ और जंगल शामिल हैं। जबकि रांची शहर ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे के मामले में महत्वपूर्ण विकास किया है, ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह गए हैं। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्वदेशी और हाशिए पर स्थित समुदायों के लोग रहते हैं, जिनमें से कई को गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह भौगोलिक अध्ययन इन बाधाओं और साक्षरता स्तरों के बीच संबंध की जांच करने का प्रयास करता है, उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां हस्तक्षेप की सबसे अधिक आवश्यकता है, और मौजूदा शैक्षिक विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है। साक्षरता की अवधारणा केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता से परे है। इसमें कार्यात्मक साक्षरता भी शामिल है, जिसमें वे कौशल होते हैं जो व्यक्तियों को अपने समुदायों और आर्थिक गतिविधियों में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए आवश्यक होते हैं। ग्रामीण रांची में, साक्षरता दर अक्सर आर्थिक विपन्नता, लिंग विषमताओं, और सीमित परिवहन नेटवर्क जैसे कारकों से प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक कारक और पारंपरिक आजीविका सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करने की जटिलता में योगदान करते हैं इस क्षेत्र में साक्षरता के अध्ययन के लिए एक भौगोलिक दृष्टिकोण आवश्यक है, क्योंकि यह शैक्षिक सुविधाओं के वितरण जैसे स्थानिक पैटर्न का विश्लेषण करने की अनुमति देता है और यह उजागर करता है कि कैसे भौगोलिक अलगाव शैक्षिक विषमताओं को बढ़ाता है। ***(गुप्ता, 2008)***

ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर सुधारने के लिए सरकारी नीतियों को वर्षों से लागू किया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान (SSA), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), और मिड-डे मील योजना जैसी पहलों को स्कूल नामांकन और बने रहने को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं शिक्षा में लिंग अंतर को दूर करने के लिए लड़कियों की शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। इन प्रयासों के बावजूद, ग्रामीण रांची में साक्षरता दर में महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर स्थित समुदायों के बीच हाल के वर्षों में, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और निजी क्षेत्र की भागीदारी ने ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों को समर्थन देने में भूमिका निभाई है। ये पहलों, जो अक्सर समुदाय-आधारित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित होती हैं, औपचारिक शिक्षा प्रणाली में कुछ अंतरालों को दूर करने में योगदान देती हैं। हालांकि, कई गाँवों और बस्तियों की भौगोलिक दूरता एक निरंतर चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि कई क्षेत्रों में नियमित स्कूल उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे, जैसे सड़कें और परिवहन की कमी है। यह अध्ययन ग्रामीण रांची में साक्षरता की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए शैक्षिक पहुंच के भौगोलिक पैटर्न का विश्लेषण और साक्षरता दर सुधारने के लिए विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। साक्षरता प्रवृत्तियों, शैक्षिक नीतियों, और शैक्षिक बुनियादी ढांचे के स्थानिक वितरण का व्यापक विश्लेषण करके, यह अध्ययन उन क्षेत्रों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा जिनमें लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह शैक्षिक परिणामों को

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

प्रभावित करने में भौगोलिक कारकों की भूमिका को उजागर करेगा और इन चुनौतियों को पार करने के लिए रणनीतियाँ सुझाएगा ताकि ग्रामीण रांची में शिक्षा तक अधिक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। ***(बोस) (प्रकाश, एन. 2016).***

साक्षरता: सामाजिक-आर्थिक विकास का आधार

साक्षरता को व्यापक रूप से एक मौलिक अधिकार और सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक माना जाता है, विशेषकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा तक पहुंच सीमित है। यह व्यक्तियों और समुदायों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह उनकी क्षमताओं का विस्तार करती है, आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ाती है, और सामाजिक समावेश को प्रोत्साहित करती है। झारखंड की राजधानी रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में, साक्षरता गरीबी के चक्र को तोड़ने, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती है। रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को कई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें उच्च स्तर की गरीबी, खराब स्वास्थ्य परिणाम, और सीमित रोजगार के अवसर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में, साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता से अधिक है; यह व्यक्तियों को श्रम बाजार में भाग लेने, सरकारी सेवाओं तक पहुंचने, और अपने जीवन स्तर को सुधारने का साधन है। साक्षरता लोगों की अपनी स्वास्थ्य, पोषण, और पारिवारिक कल्याण के बारे में उचित निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है, जिससे पूरे समुदायों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित होते हैं। हालांकि साक्षरता का सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण महत्व है, लेकिन ग्रामीण रांची अभी भी शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता के मामले में पिछड़ रहा है। भौगोलिक परिदृश्य, जिसमें पहाड़, पठार, और जंगल शामिल हैं, शिक्षा के लिए भौतिक बाधाएं उत्पन्न करता है, जबकि सामाजिक-आर्थिक विषमताएं इन चुनौतियों को और बढ़ा देती हैं। हाशिए पर स्थित समुदायों, विशेष रूप से स्वदेशी समूहों, को गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम होती है। यह अध्ययन इन चुनौतियों को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करता है और सुनिश्चित करता है कि साक्षरता ग्रामीण रांची में सामाजिक-आर्थिक विकास का एक प्रेरक बल बन सके। ***(कुमारी, 2018)***

2. संबंधित साहित्य समीक्षा

लुडलो, एट.अल., (2010), इस अध्ययन में 1985 से 1999 तक के व्यावसायिक साहित्य का विश्लेषण किया गया, ताकि विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं में काम करने वाले दूरदराज के क्षेत्रों के श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से तकनीक-समर्थित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पहचान की जा सके। डेटा संग्रह की प्रक्रिया में रेफरी पत्रिकाओं, सम्मेलनों और पेशेवर संगठनों के कार्यक्रमों की खोज शामिल थी, साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की वेबसाइटों पर इंटरनेट सर्च भी किया गया। प्रत्येक संदर्भ या रिपोर्ट से लक्षित दर्शक, वितरण तकनीक, कार्यक्रम घटक, वित्तपोषण स्रोत, और परिणामों के बारे में जानकारी एकत्र की गई। जहां आवश्यक डेटा अनुपलब्ध था, वहां कार्यक्रम की वेबसाइट, ब्रोशर या जिम्मेदार व्यक्तियों से साक्षात्कार द्वारा अधिक जानकारी प्राप्त की गई। परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि विशेष शिक्षा के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में समय के साथ तकनीकी परिवर्तन हुए हैं और अधिकांश कार्यक्रमों में मिश्रित मीडिया का उपयोग किया गया।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

यह भी निष्कर्ष निकला कि दूरस्थ शिक्षा के इन कार्यक्रमों का श्रमिकों की आपूर्ति और मांग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

बो, झोउ (2011) इस अध्ययन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शैक्षिक अवसरों में असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया। शोध में पाया गया कि दुनिया भर की सरकारों ने शिक्षा सुधार के लिए समान दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिनमें कानून बनाना, वित्तपोषण गारंटी तंत्र स्थापित करना, और शैक्षिक सुधार को प्रबंधित करने के लिए प्रबंधन प्रणाली का विकास शामिल है। विशेष रूप से, कमजोर समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई गईं, ताकि इन क्षेत्रों के स्कूलों को सुरक्षित और भरोसेमंद ढंग से सुधार किया जा सके। अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास के पीछे सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सेरोटो, जोहान्स (2011) इस अध्ययन में 1994 के बाद से दक्षिण अफ्रीका में शिक्षा में समानता और गुणवत्ता की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अश्वेत छात्रों के संदर्भ में। 1994 में एक एकीकृत स्कूल प्रणाली और नौ प्रांतीय शिक्षा विभागों की स्थापना के बावजूद, शिक्षा के लिए पर्याप्त फंडिंग और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियाँ बनी रहीं। अध्ययन में पूर्वी केप, क्वाज़ुलु-नताल और लिम्पोपो जैसे ग्रामीण प्रांतों में शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले जनसांख्यिकीय मुद्दों की समीक्षा की गई। इसमें शिक्षा के लिए रंगभेद विरासत को दूर करने के लिए अपनाए गए न्यायसंगत उपकरणों की प्रभावशीलता की आलोचना की गई। निष्कर्षों में बताया गया कि इन सुधारों के बावजूद ग्रामीण शिक्षा की स्थिति में सीमित सुधार हुए हैं। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार को ग्रामीण अश्वेत छात्रों के जीवन में सुधार लाने के लिए अधिक ठोस नीतिगत प्रयास करने की आवश्यकता है।

मैकइल्विन, एट अल., (2012) इस शोध का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों के हाई स्कूल के छात्रों के कैरियर विकास कार्यक्रमों के अनुभवों का अध्ययन करना था, जो पोस्ट-सेकेंडरी शिक्षा के लिए उनकी प्रेरणा और भागीदारी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के अठारह महीने बाद, नौ पूर्व छात्रों से उनकी यादों के बारे में सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन से तीन प्रमुख विषय उभरे: जानकारी और व्यावसायिक अवधारणाओं की पुष्टि, सामाजिक संपर्क, और सकारात्मक अनुभव। परिणामों से यह निष्कर्ष निकला कि कैरियर योजना ने छात्रों को शिक्षा और करियर के प्रति अधिक प्रेरित किया। शोध ने सुझाव दिया कि इस तरह के कार्यक्रमों के दीर्घकालिक लाभों को देखने के लिए लागत-लाभ विश्लेषण पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अबीदी, नाजिया अब्बास (2014) यह अध्ययन वित्तीय समावेशन पर केंद्रित था, जिसमें विशेष रूप से कमजोर और गरीब वर्गों को सस्ती वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों का मूल्यांकन किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा कि विकासशील देशों के अधिकांश गरीबों के पास स्थायी वित्तीय सेवाओं, जैसे बचत, ऋण या बीमा तक पहुंच नहीं है। भारत में, 135 मिलियन परिवारों को बैंकिंग सेवाओं में शामिल करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। अध्ययन से पता चला कि रांची जैसे क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर जनसंख्या, विशेषकर आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग,

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

वित्तीय सहायता के लिए गंभीर रूप से जरूरतमंद हैं। हालाँकि, इन प्रयासों की गति अभी शुरुआती चरण में है, और व्यापक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए और अधिक काम की आवश्यकता है।

सिन्हा, एट अल., (2016) इस अध्ययन में भारत में शहरीकरण की तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति और इसके प्रभावों की समीक्षा की गई। शोध में पाया गया कि वर्तमान में लगभग 28% भारतीय शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। यह अनुमान लगाया गया कि भविष्य में शहरी केंद्र सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनेंगे। शिक्षा, विशेष रूप से साक्षरता, को शहरी विकास के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक माना गया। 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में 9% की वृद्धि देखी गई, जो 2001 में 65.38% से बढ़कर 2011 में 74.04% हो गई। हालांकि, झारखंड जैसे अविकसित राज्यों में शहरीकरण और शिक्षा दोनों में ही महत्वपूर्ण कमियां बनी हुई हैं। झारखंड की निम्न साक्षरता दर के कारण विश्वसनीय मानव संसाधनों की कमी सामने आई, जिससे शहरी विकास की प्रक्रिया में रुकावटें आईं। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि झारखंड जैसे राज्यों को एकीकृत शहरी विकास योजनाओं की आवश्यकता है।

ज्योति, और सत्येंद्र किशोर (2020) इस शोध में भारत में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। अध्ययन में बताया गया कि SHG ने ग्रामीण महिलाओं को न केवल उद्यमशीलता कौशल विकसित करने में मदद की, बल्कि उन्हें बचत, जोखिम लेने और आत्मनिर्भरता की आदतें भी सिखाईं। SHG के माध्यम से महिलाओं ने एकता में शक्ति को पहचाना और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाया। हालांकि, अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमताओं को और अधिक निखारने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) को SHG प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना आवश्यक है। इस शोध का उद्देश्य SHG की महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं और कमियों की जांच करना और ICT के माध्यम से उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ाने के उपाय सुझाना था।

ज़ू, एरयोंग, जियान ली और ज़िंगचेंग ली (2021) इस अध्ययन में चीन में ग्रामीण पुनरोद्धार की प्रक्रिया और इसके तहत ग्रामीण शिक्षा प्रणाली के निर्माण की संभावनाओं की जांच की गई। अध्ययन ने ग्रामीण शिक्षा नीति चक्र (नीति डिजाइन, सामग्री, और कार्यान्वयन) का विश्लेषण किया, जिसमें अखंडता, पारदर्शिता, और अंतर्जातता को मुख्य घटक माना गया। दस प्रांतों में काम करने वाले शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों पर सर्वेक्षण के आधार पर, शोध ने पाया कि नीति डिजाइन तर्कसंगत नहीं था और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक समर्थन अपर्याप्त था। नीति के सहजीवन और एकीकरण की कमी, कमजोर प्रशासनिक ढांचा, और शिक्षक संसाधनों का अभाव, नीति निष्पादन में प्रमुख बाधाएँ बनीं। अध्ययन ने ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए पेशेवरों के लिए रैंक विस्तार और ग्रामीण-उन्मुख रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कुसियो, टॉमस, एट अल. (2022) यह अध्ययन यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित समाजशास्त्रीय और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था। पाँच यूरोपीय देशों (क्रोएशिया, जर्मनी, पोलैंड, और पुर्तगाल) में ग्रामीण उद्यमशीलता की गतिविधियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। शोध ने निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण क्षेत्रों की विकास समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय समुदायों की शिक्षा, आर्थिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्थानीय उत्पादों के उत्पादन और उनके प्रचार का समर्थन करना, और उत्पादकों व स्थानीय समुदायों

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

के बीच सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। अध्ययन ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता की रणनीतियों के विकास के लिए कई नीति सुझाव दिए।

डोनकोह, रूथ, एट अल. (2023) इस अध्ययन का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) के तहत घाना के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर शैक्षिक प्रबंधन के प्रभाव का मूल्यांकन करना था। 745 शहरी और 471 ग्रामीण शिक्षकों पर आधारित सर्वेक्षण और संरचनात्मक समीकरण मॉडल (एसईएम) के उपयोग से, अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि शैक्षिक प्रबंधन का शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर पाई गई। इंटरनेट सुविधाओं की भूमिका को भी गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण माना गया।

3. अध्ययन का महत्व

"रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता स्तर एवं शैक्षिक विकास योजनाएं - एक भौगोलिक अध्ययन" के महत्व को समझने के लिए संबंधित साहित्य समीक्षा का गहन अध्ययन महत्वपूर्ण है। **लुडलो एट अल., (2010)** के शोध से यह निष्कर्ष निकला कि दूरस्थ शिक्षा और तकनीकी सुधारों के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रमों का प्रशिक्षण सफल साबित हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि रांची जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में साक्षरता और शिक्षा की योजनाओं के लिए तकनीकी समाधानों को अपनाना आवश्यक हो सकता है। **बो, झोउ (2011)** द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार पर सरकार की नीतियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि समान नीतियों को रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है, जिससे शैक्षिक अवसरों में सुधार संभव है। **सेरोटो, जोहान्स (2011)** के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि पर्याप्त फंडिंग और बेहतर नीतियों की कमी के कारण ग्रामीण शिक्षा में सुधार में बाधा उत्पन्न होती है। इसी तरह, रांची जिले में भी शिक्षा के लिए सरकारी नीतियों में सुधार की आवश्यकता है। **मैकइल्विन, एट अल., (2012)** ने ग्रामीण इलाकों के छात्रों के कैरियर विकास कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला, जो रांची के ग्रामीण छात्रों के शैक्षिक प्रोत्साहन के लिए प्रासंगिक हो सकता है। **अबीदी (2014)** का शोध रांची के आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों की वित्तीय समावेशन की आवश्यकता को उजागर करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा योजनाओं के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी आवश्यक है। **सिन्हा, एट अल., (2016)** के अध्ययन ने शहरीकरण और साक्षरता के बीच के संबंध पर जोर दिया, जो रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण और शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है। **ज्योति और सत्येंद्र किशोर (2020)** ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के महत्व को समझाया, जो रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। **ज़ू, एरयोंग, एट अल. (2021)** और **कुसियो, एट अल. (2022)** द्वारा ग्रामीण शिक्षा प्रणाली के पुनरोद्धार और उद्यमशीलता पर दिए गए विचार रांची जिले के शिक्षा और विकास योजनाओं के सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अंत में, **डोनकोह, एट अल. (2023)** ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक प्रबंधन और इंटरनेट सुविधाओं के महत्व को रेखांकित किया, जो रांची जिले के शैक्षिक विकास के लिए प्रासंगिक है।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

4. ग्रामीण क्षेत्रों के साक्षरता में चुनौतियाँ

4.1 भौगोलिक अलगाव और अवसंरचना की चुनौतियाँ

रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक इसका चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिदृश्य है। इस जिले की पहचान पहाड़ी क्षेत्र, पठार, और घने जंगलों से होती है, जो शैक्षिक सुविधाओं तक पहुँच को कठिन बनाता है।

- **दूरदराज के गाँव:** कई गाँव दूरस्थ और अलगाव में स्थित हैं, जो नजदीकी स्कूल से काफी दूर हैं।
- **अवसंरचना की कमी:** सड़कें और सार्वजनिक परिवहन की कमी समस्या को और बढ़ा देती है, जिससे बच्चों के लिए स्कूल पहुँचना शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

इन पहुँच संबंधी समस्याओं के अलावा, इन गाँवों की दूरस्थ स्थिति अक्सर शैक्षिक संसाधनों की कमी का कारण बनती है, जिसमें योग्य शिक्षक, पाठ्यपुस्तकें, और अध्ययन सामग्री शामिल हैं। शिक्षकों को इन क्षेत्रों में काम करने में हिचक होती है, क्योंकि रहने की स्थिति और अलगाव खराब होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की कमी होती है। ये भौगोलिक बाधाएँ न केवल शिक्षा तक पहुँच को सीमित करती हैं बल्कि सीखने की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती हैं, जिससे ग्रामीण छात्रों के लिए कार्यात्मक साक्षरता हासिल करना और कठिन हो जाता है। ***(सिंह, 2010) (चौधरी)***

4.2 सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ और सांस्कृतिक बाधाएँ

सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- **गरीबी:** इन क्षेत्रों में कई परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, और शिक्षा अक्सर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की प्राथमिकता के मुकाबले पीछे रह जाती है।
- **बाल श्रम:** बच्चे अक्सर खेतों में काम करके या पारिवारिक व्यवसायों में भाग लेकर घरेलू आय में योगदान देने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे स्कूल जाने का समय बहुत कम रह जाता है।
- **शिक्षा की लागत:** शिक्षा से जुड़ी लागतें, जैसे कि स्कूल सामग्री, वर्दी, और परिवहन, वित्तीय बोझ बन जाती हैं, जिसे कई ग्रामीण परिवार सहन नहीं कर पाते।

सांस्कृतिक कारक भी इन सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को बढ़ाते हैं। लिंग विषमताएँ एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई हैं, क्योंकि कई परिवार लड़कों की शिक्षा को लड़कियों की शिक्षा पर प्राथमिकता देते हैं। ग्रामीण समुदायों में पारंपरिक मानदंड अक्सर लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित करते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्कूल के बाद। बाल विवाह और घरेलू जिम्मेदारियाँ लड़कियों की शैक्षिक अवसरों को और सीमित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता दर में एक स्पष्ट लिंग अंतर पैदा होता है। ये सामाजिक-आर्थिक और

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

सांस्कृतिक बाधाएँ मिलकर शैक्षिक प्रगति में रुकावट डालती हैं और ग्रामीण रांची में साक्षरता के निम्न स्तर को बनाए रखती हैं। ***(ज्योति, 2020)***

5. सरकारी और गैर-सरकारी पहल और साक्षरता पर उनका प्रभाव

5.1 साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सरकारी पहलें

भारतीय सरकार ने विशेष रूप से रांची जिले जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दरों को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। इनमें से एक प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान (SSA) है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच हासिल करना है। SSA दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति और मुफ्त पाठ्यपुस्तकें एवं वर्दियाँ प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे शिक्षा के लिए आर्थिक बाधाएँ कम हों। दूसरी महत्वपूर्ण पहल अधिकारिता अधिनियम (RTE) है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देती है, यह सुनिश्चित करती है कि हर बच्चा, चाहे उसका सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कैसा भी हो, स्कूल जाने का अवसर प्राप्त करे। मिड-डे मील योजना ने भी छात्रों को मुफ्त भोजन प्रदान करके स्कूल में उपस्थिति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भूख को कम किया जा सके और माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम विशेष रूप से शिक्षा में लिंग असमानता को लक्षित करता है, जो लड़कियों की शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देता है और उन भेदभावपूर्ण प्रथाओं को हतोत्साहित करता है जो उनके अवसरों को सीमित करती हैं। ये पहलें मिलकर उन मुख्य बाधाओं को संबोधित करने का प्रयास करती हैं, जैसे गरीबी, लिंग असमानता, और भौगोलिक अलगाव, जो ग्रामीण रांची में प्रचलित हैं।

5.2 सरकारी नीतियों का प्रभाव और चुनौतियाँ

हालांकि इन सरकारी पहलों ने ग्रामीण रांची में साक्षरता दर को सुधारने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी उनके प्रभाव को पूरी तरह से महसूस करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। SSA के तहत स्कूलों का निर्माण उपलब्धता बढ़ाने में सफल रहा है, लेकिन इनमें से कई स्कूल उचित ढाँचे, जैसे कक्षाओं, स्वच्छता सुविधाओं और शिक्षण संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण शिक्षा की गुणवत्ता को और सीमित करते हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि मिड-डे मील योजना ने नामांकन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, उच्च कक्षाओं में उच्च ड्रॉपआउट दरें अभी भी एक चिंता का विषय हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ने स्कूलों में महिला नामांकन बढ़ाने में सकारात्मक परिणाम देखे हैं, फिर भी, विशेष रूप से वंचित और आदिवासी समुदायों में, साक्षरता में लिंग असमानता बनी हुई है। भौगोलिक दूरियाँ, जो खराब परिवहन नेटवर्क से बढ़ जाती हैं, नियमित स्कूल उपस्थिति में भी बाधा डालती हैं। यह अध्ययन यह बताता है कि जबकि सरकारी पहलों ने साक्षरता को सुधारने के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया है, निरंतर प्रयासों को अवसंरचनात्मक अंतर, शिक्षक की गुणवत्ता, और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि ग्रामीण रांची में समान शैक्षिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

5.3 शैक्षिक अंतराल को भरने में NGOs की भूमिका

गैर-सरकारी संगठन (NGOs) ग्रामीण क्षेत्रों जैसे रांची में शैक्षिक अंतराल को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां सरकारी प्रयास अक्सर अपर्याप्त होते हैं। ये संगठन विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विशेष रूप से दूरदराज के गांवों में जहां औपचारिक स्कूल या तो गैर-मौजूद हैं या भौगोलिक अलगाव के कारण अप्राप्य हैं। NGOs ने अनौपचारिक स्कूल, मोबाइल शिक्षा इकाइयाँ, और सामुदायिक शिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं, जो ग्रामीण जनसंख्या की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये अनौपचारिक स्कूल अक्सर उन बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र स्रोत होते हैं, जो दूरी या आर्थिक बाधाओं के कारण सरकारी स्कूलों में जाने में असमर्थ होते हैं। NGOs का एक महत्वपूर्ण योगदान उनकी लचीलापन है, जिससे वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों को अनुकूलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई संगठन अपने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक प्रशिक्षण और जीवन कौशल शामिल करते हैं, जिससे छात्रों को ऐसे व्यावहारिक कौशल मिलते हैं जो उनके समुदाय की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त, NGOs अक्सर वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित करते हुए, जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गई हैं। ये कार्यक्रम वयस्कों को बुनियादी साक्षरता कौशल प्राप्त करने में मदद करते हैं और उन्हें अपने समुदायों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाते हैं।

5.4 सामुदायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण

सामुदायिक शिक्षा पहलों, जो अक्सर NGOs या स्थानीय समुदाय के नेताओं द्वारा संचालित होती हैं, रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा प्रणाली को पूरक बनाने में महत्वपूर्ण होती हैं। ये पहलें विशेष रूप से कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां व्यक्ति अर्थपूर्ण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करते हैं। कई सामुदायिक कार्यक्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित होते हैं, जो कृषि, हस्तशिल्प, और छोटे पैमाने पर उद्यमिता जैसे व्यावहारिक कौशल सिखाते हैं, जो ग्रामीण परिवारों की आजीविका के लिए आवश्यक होते हैं। ***(अली)*** ये पहलें अक्सर अत्यधिक स्थानीयकृत होती हैं, जिससे सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होती है जो ग्रामीण जनसंख्या की पारंपरिक आजीविका और जीवनशैली के साथ गूंजती है। जहां औपचारिक शिक्षा प्रणाली सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होती है, वहां सामुदायिक आधारित हस्तक्षेप एक लचीला और अनुकूलनशील समाधान प्रदान करते हैं। (***चौधरी, 2017)***

6. निष्कर्ष

इस अध्ययन ने रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया है, जो सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रेरित करती है। भौगोलिक अलगाव, आर्थिक विषमताएँ, और सांस्कृतिक कारक इस क्षेत्र में सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं। शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों के बावजूद, बुनियादी ढाँचे, शिक्षक की गुणवत्ता, और सांस्कृतिक मानदंडों के संदर्भ में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों में। भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मानचित्रण ने उन क्षेत्रों को उजागर किया है जहाँ शैक्षणिक बुनियादी ढाँचा कमजोर है, जिससे लक्षित हस्तक्षेप

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए, प्रयासों को शैक्षणिक पहुँच को बढ़ाने, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को संबोधित करने, और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दरों में दीर्घकालिक सुधार को बढ़ावा मिल सके।

संदर्भ

1. लुडलो, बारबरा एल., और सारा ए. ब्रैनन। "ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कर्मियों को तैयार करने वाले दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम: वर्तमान अभ्यास, उभरते रुझान और भविष्य की दिशाएँ।" ग्रामीण विशेष शिक्षा त्रैमासिक 29.3 (2010): 4-15।
2. बो, झोउ। "सभी सरकारों में शहरी और ग्रामीण शिक्षा के समग्र विकास को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों की सामान्यता।" 2011 इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल इंजीनियरिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ।IEEE, 2011।
3. सेरोटो, जोहान्स। "1994 से दक्षिण अफ्रीका के तीन प्रांतों में ग्रामीण शिक्षा का प्रावधान: स्कूल सुधार के लिए निहितार्थ।" जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल स्टडीज़ 2011.si-1 (2011): 138-152।
4. मैकइल्विन, पीटर, तान्या मॉर्गन, और जेनिफर बिमरोज़। "ग्रामीण स्कूली छात्रों के लिए करियर विकास कार्यक्रम के अनुभव का एक अनुदैर्ध्य अध्ययन।" ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ करियर डेवलपमेंट 21.1 (2012): 22-30.
5. पाल, जी.ओ.वी.आई.एन.डी., एट अल. "झारखंड के रांची और खूंटी जिले में लाख उत्पादकों का सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल।" ग्रामीण और कृषि अनुसंधान जर्नल 13.2 (2013): 1-5.
6. आबिदी, नाजिया अब्बास। "सस्टेनेबल फाइनेंशियल इनक्लूजन: रांची जिले का एक केस स्टडी।" क्लियर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 5.6 (2014) ।
7. सिन्हा, एआर राजन चंद्र, सत्यकी सरकार, और बिमल चंद्र रॉय। "झारखंड, भारत के कम विकसित राज्यों के लिए साक्षरता सुधार के माध्यम से शहरी विकास को बढ़ावा देना।"
8. कुमारी, वर्षा, और ओ.पी. मिश्रा। "रांची, झारखंड में जलवायु परिवर्तन के संबंध में किसानों का अनुकूलन व्यवहार।" भारतीय पारिस्थितिक समाज: 53.2017
9. अनीसाह, आर., वी. वी. नीथू, और वी. माधा सुरेश। "भारत के झारखंड के रांची शहर में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों का एक सामाजिक-आर्थिक अध्ययन।" (2019)।
10. ज्योति, और सत्येंद्र किशोर। "झारखंड के रांची जिले में ग्रामीण और शहरी महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमताओं का एक सामाजिक-आर्थिक अध्ययन और उनकी क्षमताओं को बदलने के लिए आईसीटी की आवश्यकता।" स्मार्ट इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग और अनुप्रयोग: स्मार्ट कंप्यूटिंग और सूचना विज्ञान पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही, खंड 2। स्प्रिंगर सिंगापुर, 2020।
11. ज़ू, एरयोंग, जियान ली, और जिंगचेंग ली। "चीन में ग्रामीण पुनरोद्धार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का सतत विकास: एक व्यापक नीति चक्र विश्लेषण।" स्थिरता 13.23 (2021): 13101.
12. कुसियो, टॉमस, एट अल. "क्या यूरोपीय देशों के भीतर ग्रामीण विकास चुनौतियों में कोई अंतर है? यूरोपीय संघ के ग्रामीण नेताओं से सामाजिक और आर्थिक संदर्भ।" अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि व्यवसाय प्रबंधन समीक्षा 25.5 (2022): 737-756.
13. डोनकोह, रूथ, एट अल. "घाना में ग्रामीण और शहरी प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर शैक्षिक प्रबंधन के प्रभाव।" हेलियॉन 9.11 (2023) ।
14. गुप्ता, एस., और नंदा, पी. (2008)। रांची (झारखंड) की जनजातीय आबादी के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन। जोहार, 3(2), 57।
15. बोस, ए. आर.टी.ई. एक दशक बाद।

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

16. प्रकाश, एन. (2016). भारत में शिक्षा: आरटीई की भूमिका, इसकी उपलब्धियाँ और आगे की चुनौतियाँ। समाजबोध, 6(1), 46-59.
17. कुमारी, एन. (2018)। सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता का एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन: ओरमांझी ब्लॉक, रांची का एक केस स्टडी। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च, 59(5)।
18. सिंह, ए.के. (2010). शहरीकरण और जनजातीय विकास: झारखंड के रांची जिले का एक केस स्टडी। 21वीं सदी में विकास संबंधी चिंताएँ, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 277-294
19. चौधरी, बी. ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अंतरजिला भिन्नता और झारखंड में कृषि विकास पर इसका प्रभाव। संकल्प प्रकाशन।
20. ज्योति, और किशोर, एस. (2020)। झारखंड के रांची जिले में ग्रामीण और शहरी महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमताओं का एक सामाजिक-आर्थिक अध्ययन और उनकी क्षमताओं को बदलने के लिए आईसीटी की आवश्यकता। स्मार्ट इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग और एप्लीकेशन में: स्मार्ट कंप्यूटिंग और सूचना विज्ञान पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही, खंड 2 (पृष्ठ 111-122)। स्प्रिंगर सिंगापुर।
21. चौधरी, एस. के. (2017)। एनजीओ, शिक्षा और जनजातियाँ: झारखंड, भारत का एक अनुभवजन्य अध्ययन। एजुकेशनल क्वेस्ट-एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड एप्लाइड सोशल साइंसेज, 8(3), 531-541।
22. अली, पी. एस. ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका।